

लोकसभा में पीएम की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पास

2004 के बाद ऐसा पहली बार, कांग्रेस बोली... जब तक राहुल नहीं बोलेंगे पीएम को नहीं बोलने देंगे

नई दिल्ली, 05 फरवरी 2026। बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया। 2004 के बाद पहली बार यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना पास हुआ है। इससे पहले 10 जून 2004 को विपक्ष ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने दिया था। गुरुवार को लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इस पर स्पीकर ने पहली बार 65 सेकंड के भीतर, दूसरी बार 5 मिनट में और तीसरी बार 2 मिनट में कार्यवाही स्थगित कर दी। लोकसभा 3 बजे दोबारा शुरू हुई लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच कांग्रेस के लोकसभा से निलंबित सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि जब तक लोकसभा में राहुल गांधी को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती, तब तक विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने नहीं देगा।



स्पीकर ने नारा नहीं दिया गया है। यह भी साफ नहीं है कि हमारे किसानों के हितों की रक्षा होगी या नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा- अब जब छपी हुई किताब पेश की जा रही है, तो उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। हर सांसद को संसद में अपनी बात कहने का हक है।

राज्यसभा में भी राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोकने के मुद्दे पर हंगामा

राज्यसभा में भी राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोकने के मुद्दे पर हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल को पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब पर नहीं बोलने दिया, मैं उसपर यहाँ बोलूँगा। इस पर उपसभापति ने उन्हें रोक दिया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे से कहा- राहुल गांधी निराम नहीं मानते, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं। जेपी नड्डा ने भी खड़गे से कहा कि राज्यसभा में लोकसभा का मुद्दा नहीं उठा सकते। आप कांग्रेस को अबोध बालक का बंधक न बनाएं।

सांसद डिंपल यादव बोली... हर सांसद को संसद में अपनी बात कहने का हक

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा- डील पर सरकार की तरफ से कोई

जो कह रहे हैं, वे और क्या कर सकते हैं। उनकी स्क्रिप्ट और शब्द सीमित हैं। नड्डा आलोचना के लिए बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि शब्दों की कमी राजनीतिक संकीर्ण सोच की निशानी है।

जेपी नड्डा बोले- पार्टी को अबोध बालक का बंधक न बनाएं

राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी कल तैयार बैठे थे, वहाँ (लोकसभा) जो भी चीजें हुईं, उनका जवाब देने के लिए। आपने सदन ही नहीं चलने दिया। अब यहाँ भी यही कर रहे हैं। आप बहुत सीनियर हैं। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विपक्ष के नेता खड़गे को नसीहत दी कि आप अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी चलाइए। इस पर खड़गे ने कहा कि आपने जो नाबालिग जैसा हिंदी में कुछ कहा वह ठीक नहीं है। आप किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मुझे आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं वह ठीक नहीं है। दोनों सदन मिलकर चलते हैं। एक और बात बार-बार मत टोकें कि हमारी पार्टी कैसी है। आपकी पार्टी को तो मोदी जी ने बंधक बना रखा है।

प्रियंका बोली... राहुल को बोलने दें... वे डर क्यों रहे...

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्वा ने कहा... उन्हें एलओपी को बोलने देना चाहिए। उन्हें राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए। वे किस बात से डर रहे हैं। क्या वे इस बात से डर रहे हैं कि वह किसी किताब से कुछ कोट करेंगे। क्या वे इस बात से डर रहे हैं कि हम उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने यह ट्रेड डील की है, जिसके तहत सभी किसानों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है।

राज्यसभा में पीएम बोले... कांग्रेस के वक्त डील यानी बोफोर्स घोटाला, ये मोहब्बत की दुकान मोदी की कब्र खोदने की बात करती है, विपक्ष का वॉकआउट

नई दिल्ली, 05 फरवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। स्पीच के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खड़गे जी की उम्र देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की इजाजत दी जाए। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री ने एक घंटा 27 मिनट भाषण दिया। मोदी ने कहा कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, जो मोदी की कब्र खोदने की बात करती है। ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का अपमान नहीं है। पीएम बोले- टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, डीएमके दशकों से केंद्र में सत्ता का हिस्सा रहे। उनकी पहचान क्या बनी, उनके वक्त डील के नाम पर बोफोर्स याद आता है। आज डील की चर्चा गौरव से होती है।



गांव ऐसे थे, जिनको बिजली का मतलब नहीं पता था। हमने वहाँ बिजली वहाँ पहुँचाई इसलिए ये मोदी की कब्र खोदने के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिखता।

पीएम ने कहा- कांग्रेस ने परिवार के लिए देश को दांव पर लगाया

पीएम ने कहा कि मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी है, उसका परिणाम है इसलिए ये मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस के शाही परिवार को देश ने दशकों तक अवसर दिया देश ने अपना भविष्य दांव पर लगाया, लेकिन आपने परिवार के लिए देश को दांव पर लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल किले से गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया, लेकिन गरीबी हटाने के लिए क्या किया किसी ने नहीं बताया। मैं देश के गरीबों को सलाह करता हूँ, उन्होंने हमारी नीतियों पर नीयत पर भरोसा किया और अपने आप को खपाने में कोई कमी नहीं रखी।

पीएम बोले- 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को पीछे छोड़ा

पीएम ने कहा कि आज 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को पीछे छोड़ा है। आज वे हमारे साथ चल रहे हैं। 2014 के पहले रेलवे क्रॉसिंग से स्कूल की बस जाती थीं, 20-20 बच्चों की मौत खबर आती थी। हमने सारे क्रॉसिंग बंद की इसलिए ये मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा- 2014 से पहले 18 हजार

आसाराम के अहमदाबाद आश्रम पर चलेगा बुलडोजर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमीन वापस लेने का आदेश दिया

अहमदाबाद, 05 फरवरी 2026। अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित आसाराम का मुख्य आश्रम अब कानूनी विवादों में है। गुजरात हाईकोर्ट ने 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की आश्रम की जमीन को राज्य सरकार के कब्जे में लेने और आश्रम में बने अवैध निर्माणों को हटाने की मंजूरी दे दी है। इस आश्रम की जगह अब 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। वर्तमान में इस जमीन की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की है। गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वैभववी नानावटी ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विकास परियोजना की आवश्यकता और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सरकारी कार्रवाई उचित है। इस फैसले के बाद अहमदाबाद नगर निगम अब किसी भी समय अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।



अतिक्रमण करना और फिर उसे वैध ठहराना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आश्रम को कानूनी रूप से आवश्यक संख्या से अधिक नोटिस भेजे गए, एक के बाद एक कई सुनवाई भी हुईं। प्रशासन को जांच के दौरान पता चला कि इन इकाइयों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के लिए किया जा रहा था। नियमों के उल्लंघन और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोपों के चलते कलेक्टर कार्यालय की ओर से भी आश्रम को कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है। राज्य अधिकारियों ने अदालत के सामने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कि दशकों पहले सीमित धार्मिक उपयोग के यह भूमि आवंटित की गई थी।

32 अवैध युनिट स्थापित हो रहीं आश्रम में

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ लोक अभियोजक जीएच विर्क ने तर्क दिया कि मोटेरा स्थित आश्रम परिसर में करीब 32 अवैध युनिट स्थापित कर ली गई थीं। जबकि सार्वजनिक भूमि पर धीरे-धीरे

अतिक्रमण करना और फिर उसे वैध ठहराना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आश्रम को कानूनी रूप से आवश्यक संख्या से अधिक नोटिस भेजे गए, एक के बाद एक कई सुनवाई भी हुईं। प्रशासन को जांच के दौरान पता चला कि इन इकाइयों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के लिए किया जा रहा था। नियमों के उल्लंघन और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोपों के चलते कलेक्टर कार्यालय की ओर से भी आश्रम को कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है। राज्य अधिकारियों ने अदालत के सामने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कि दशकों पहले सीमित धार्मिक उपयोग के यह भूमि आवंटित की गई थी।

मप्र के जबलपुर में स्थापित होगा देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल ट्रेनिंग सिम्युलेटर

नई दिल्ली, 05 फरवरी 2026। मध्य प्रदेश पाँच जेनरेटिंग कंपनी (एमपीजीसीएल) जबलपुर के नयागांव स्थित पाँच जेनरेटिंग प्रशिक्षण संस्थान में लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत से देश का सबसे बड़ा मल्टी-फंक्शनल थर्मल और हाइड्रो ऑपरेटिंग ट्रेनिंग सिम्युलेटर स्थापित करने जा रही है। कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन व प्रशासन) दीपक कुमार करयप ने गुरुवार को बताया कि इस अत्याधुनिक सिम्युलेटर के माध्यम से विद्युत उत्पादन अभियंताओं को विद्युत संयंत्रों के संचालन, नियंत्रण एवं आपातकालीन परिस्थितियों के प्रबंधन का यथार्थपरक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे प्लांट ट्रिपिंग जैसी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी। यह सिम्युलेटर रिमोट ऑपरेशन की सुविधा से भी युक्त होगा। इससे पाँच जेनरेटिंग प्रशिक्षण संस्थान न केवल राज्य बल्कि अन्य राज्यों की विद्युत कंपनियों के अभियंताओं एवं तकनीकी विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में स्थापित होगा।

चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों से कहा- पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करें

नई दिल्ली, 05 फरवरी 2026। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सामान्य, पुलिस तथा व्यव पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। यहां के भारतीय निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में गुरुवार से शुरू यह दो दिवसीय बैठक तीन चरणों में होगी। आयोग के अनुसार कुल 1,444 अधिकारियों को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया है, जिनमें 714 सामान्य पर्यवेक्षक, 233 पुलिस पर्यवेक्षक और 497 व्यव पर्यवेक्षक शामिल हैं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जनेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को संबोधित किया। जनेश कुमार ने कहा कि पर्यवेक्षकों को आयोग के मार्गदर्शक दीपक के रूप में चुना गया है। पर्यवेक्षकों को मौजूदगी 824 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी मशीनरी को ऊर्जा प्रदान करेगी और वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करें।

देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का शुभारंभ

नई दिल्ली, 05 फरवरी 2026। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को विज्ञान भवन से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी को आगामी तीन वर्षों के भीतर पूरे देश में शुरू किया जाएगा और यह टैक्सी चालकों के आर्थिक सशक्तीकरण का एक बड़ा माध्यम बनेगी। अमित शाह ने कहा कि फिलहाल भारत टैक्सी की शुरुआत गुजरात के कुछ शहरों के साथ दिल्ली और एनसीआर में की जा रही है लेकिन अगले तीन साल से भी कम समय में यह देश के हर राज्य और प्रमुख शहरों में उपलब्ध होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्रारका से कामाख्या तक भारत टैक्सी टैक्सी चालकों के कल्याण का एक सशक्त मॉडल बनेगी। टैक्सी चालकों को 'सारथी'



की संज्ञा देते हुए शाह ने कहा कि अभी तक उनकी टैक्सी का पहिया किसी और की कमाई करता था, लेकिन भारत टैक्सी के माध्यम से अब वही पहिया उनकी अपनी कमाई और समृद्धि के लिए घूमेगा। उन्होंने कहा कि सहकार टैक्सी जो भी मुनाफा कमाएगी, उसमें से तीन वर्ष बाद केवल 20 प्रतिशत राशि सहकार टैक्सी के पास रहेगी, जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि प्रति कारिलीमीटर की औसत के आधार पर सीधे सारथियों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। सहकार टैक्सी के मालिक भी स्वयं सारथी ही होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी देश की माताओं और

बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने 'सारथी दीदी' की अवधारणा का उल्लेख करते हुए बताया कि ऐप पर एक अलग विंडो के माध्यम से महिला यात्रियों के लिए महिला चालक उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी यात्रा और अधिक सुरक्षित हो सकेगी। शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार टैक्सी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, बल्कि सहकारिता टैक्सी क्षेत्र में कदम रख रही है। सहकारिता का मूल उद्देश्य यह है कि छोटे-छोटे संसाधनों वाले लोग मिलकर बड़े कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि सहकारिता टैक्सी क्षेत्र में कदम रख रही है। सहकारिता का मूल उद्देश्य यह है कि छोटे-छोटे संसाधनों वाले लोग मिलकर बड़े कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि सहकारिता टैक्सी क्षेत्र में कदम रख रही है। सहकारिता का मूल उद्देश्य यह है कि छोटे-छोटे संसाधनों वाले लोग मिलकर बड़े कार्य कर सकें।

भारत टैक्सी के संचालन में लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, जिसमें हर पांच साल में सारथियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे और चालकों के हितों की रक्षा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सहकार टैक्सी लिमिटेड ने भारत टैक्सी के विस्तार के लिए कई संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अमित शाह की उपस्थिति में कुल नौ एमओयू का आदान-प्रदान किया गया, जिनमें भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग, दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड, जीएमआर, इफिको टोकियो, भारतीय स्टेट बैंक और पेट्रोएम् शक्ति शामिल हैं। इस अवसर पर अमित शाह ने प्रतीकात्मक रूप से पांच सारथी भाई-बहनों को भारत टैक्सी के शेर प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।

भारत को हिंदुत्व पर गर्व है और हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है : मोहन यादव

भोपाल, 05 फरवरी 2026। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वैचारिक स्तर पर भारत को हिंदुत्व पर गर्व है, हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है। सनातन की धारा शाश्वत रूप से बहती रहे, इस उद्देश्य से संतवृंद और सरकार समन्वित रूप से प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति को नए आयाम तक पहुंचाने में आदि शंकराचार्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश की धरा से आदि शंकराचार्य का विशेष संबंध रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट के आयोजित गुरुदेव समाधि मंदिर



मूर्ति स्थापना समारोह के अंतर्गत संत सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट द्वारा स्थापित भारत माता मंदिर समाज और राष्ट्र में ऊर्जा का संचार कर रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का जूनापीठाधीश्वर आचार्य महा-मंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने सिंहरथ-2028 के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आदि शंकराचार्य की परंपरा के संवाहक, वैदिक सनातन

संस्कृति के उन्नायक देश के प्रथम भारत माता मंदिर के संस्थापक पद्मभूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भव्य और दिव्य सिंहरथ के आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाओं और विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत महात्माओं को सिंहरथ-2028 के लिए उज्जैन पधारने के लिए निमंत्रण दिया। समारोह में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि संतवृंद के आशीर्वाद से देश में पिछले वर्षों में हुआ बदलाव अद्भुत है।

ममता सरकार का बड़ा ऐलान... माध्यमिक पास बेरोजगारों को भता, डीए में बढ़ोतरी और सिविक वॉलंटियर्स के वेतन में इजाफा

कोलकाता, 05 फरवरी 2026। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व गुरुवार को अपना आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। राज्य की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत इस बजट में आम लोगों, सरकारी कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं और सामाजिक सेवा से जुड़े कर्मियों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। बजट का सबसे बड़ा आकर्षण माध्यमिक पास बेरोजगार युवाओं के लिए नई भत्ता योजना रही। 'बांग्ला युव साथी' नाम की इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष की आयु के माध्यमिक उतीर्ण बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रति माह 1500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। यह योजना आगामी 15 अगस्त से लागू होगी और अधिकतम पांच वर्षों तक इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं के लोकप्रिय कल्याणकारी कार्यक्रम 'लक्ष्मी भंडार' में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। योजना के तहत मिलने वाली राशि में प्रति माह 500 रुपये की वृद्धि की गई है।

गृह निर्माण मंडल में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश... उपायुक्त 60 हजार लेते ट्रैप, वरिष्ठ सहायक भी गिरफ्तार

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 05 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल वृत्त अम्बिकापुर में रिश्वतखोरी का गंभीर मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की ट्रैप कार्रवाई में उपायुक्त (अधीक्षण अभियंता) पूनम चंद अग्रवाल को 60 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस मामले में वरिष्ठ सहायक ग्रेड-2 अनिल सिन्हा को भी रिश्वत की राशि लेने और लेन-देन में भूमिका निभाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई सरकारी निर्माण कार्यों के भुगतान और सत्यापन प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती है। मामले के सामने आने के बाद विभागीय हलकों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार रवि कुमार नामक ठेकेदार ने वर्ष 2023 में हाउसिंग बोर्ड कार्यालय अम्बिकापुर से दो महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की निविदा भरी थी। इनमें नवीन तहसील भवन दौरा-कुचली, जिला बलरामपुर तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लुण्डा में छह अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कार्य शामिल था। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने के बाद भी विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया। तहसील



रकम बढ़कर 65 हजार की मांग

ट्रैप के दौरान उपायुक्त ने रिश्वत की रकम वरिष्ठ सहायक अनिल सिन्हा को देने के लिए कहा। वरिष्ठ सहायक ने ठेकेदार को बताया कि 60 हजार नहीं बल्कि 70 हजार रुपए देने होंगे। बाद में सौदा कम से कम 65 हजार रुपए में तय किया गया। ठेकेदार से अतिरिक्त 5 हजार रुपए लेकर कुल 65 हजार रुपए की रिश्वत राशि तैयार की गई। इसमें से 5 हजार रुपए अनिल सिन्हा ने अपने पास रख लिए और शेष 60 हजार रुपए उपायुक्त पूनम चंद अग्रवाल को कार्यालय में जाकर दिए गए।

भवन के निर्माण कार्य का लगभग 28 लाख रुपए तथा विद्यालय भवन निर्माण का लगभग 7.50 लाख रुपए भुगतान लंबित था। ठेकेदार रवि कुमार ने बताया कि निर्माण पूर्ण होने के बाद विभागीय भौतिक सत्यापन और अंतिम समयवृद्धि की अनुशंसा आवश्यक

थी। इसी प्रक्रिया के एवज में उपायुक्त पूनम चंद अग्रवाल द्वारा एक लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई। इससे परेशान होकर ठेकेदार ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने सत्यापन प्रक्रिया शुरू की।

सत्यापन में 60 हजार में बनी सहमति

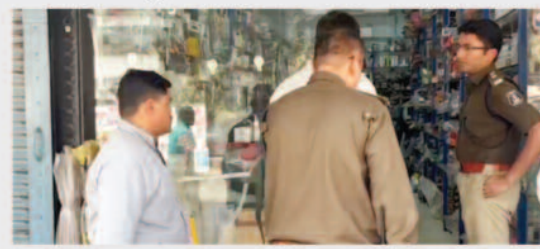
शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी ने दोनों निर्माण कार्यों के लिए 30-30 हजार रुपए के हिसाब से कुल 60 हजार रुपए रिश्वत लेने की सहमति दी। इसके बाद एसीबी द्वारा 5 फरवरी को ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई।

रिश्वत की रकम वरिष्ठ, दोनों आरोपी गिरफ्तार

जैसे ही ठेकेदार ने तय संकेत दिया, ट्रैप दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उपायुक्त के पास से 60 हजार रुपए तथा वरिष्ठ सहायक के पास से 5 हजार रुपए बरामद कर जब्त कर लिए। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 12 (पीसी एक्ट 1988, संशोधन 2018) के तहत कार्रवाई की गई है। आगे की जांच जारी है और विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की संभावना बताई जा रही है।

स्कूल के सामने मोबाइल दुकान में छापा...60 पैकेट प्रतिबंधित ई-सिगरेट व चाकू जब्त, संचालक गिरफ्तार

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 05 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।



मैडिकल कॉलेज अस्पताल के समीप स्थित शासकीय स्कूल के सामने संचालित एक मोबाइल व गिफ्ट गैलरी दुकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित ई-सिगरेट और चाकू बरामद किए गए हैं। गुरुवार दोपहर मणिपुर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने सीएसपी राहुल बंसल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की।



भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के बावजूद दुकान संचालक लंबे समय से इसका अवैध कारोबार कर रहा था। स्कूल के पास दुकान होने के कारण कई बच्चे भी इसकी लत के संपर्क में आ रहे थे। जानकारी के अनुसार मणिपुर शासकीय स्कूल के सामने स्थित अमित मोबाइल व गिफ्ट गैलरी का संचालन अमित अग्रवाल करता है। स्कूल प्रबंधन को बच्चों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव की चिंता थी। शिक्षकों ने इसकी

जानकारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी राजेश अग्रवाल को अवगत कराया गया। इसके बाद संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

60 पैकेट ई-सिगरेट जब्त : छपेमारी के दौरान टीम ने दुकान से 60 पैकेट ई-सिगरेट और चाकू बरामद कर जब्त

किए। आरोपी संचालक अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

ई-सिगरेट सामान्य सिगरेट से अधिक घातक : थाना प्रभारी सीपी तिवारी और आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि ई-सिगरेट भारत में प्रतिबंधित है और इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है।

रजत जयंती समारोह में उपभोक्ताओं का सम्मान विद्युत विभाग ने विकास यात्रा प्रदर्शनी लगाई पीएम सूर्य घर योजना की दी जानकारी

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 05 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा भैयाथान कार्यालय परिसर में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही। समारोह में कंपनी की 25 वर्षों की उपलब्धियों, विद्युत सेवा विस्तार तथा उपभोक्ताओं के सहयोग को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। इस अवसर पर बीपीएल कनेक्शन के अनुदान पाने वाले उपभोक्ताओं तथा दो वर्षों से नियमित बिजली बिल भुगतान करने वाले घरेलू, कृषि और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर



सम्मानित किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभान्वित उपभोक्ताओं को भी सम्मान प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि ने विद्युत क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट स्थापना पर मिलने वाली सब्सिडी का अधिकाधिक लाभ उठाने की

अपील की। भैयाथान के सहायक अभियंता ने बताया कि क्षेत्र में दो 33/11 केवी उपकेंद्र तथा पांच 11 केवी फीडर कार्यरत हैं। साथ ही 47 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण किया जा चुका है। कार्यक्रम में कंपनी की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। संचालन कनिष्ठ अभियंता समय लाल बंजारे ने किया।

मछली व्यवसायियों से लूट व अपहरण... कोलकाता से आए कारोबारी को अगवा कर मांगी फिरोती, दो आरोपी गिरफ्तार

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 05 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता से मछली व्यवसाय के सिलसिले में अम्बिकापुर आए कारोबारी और उसके साथी के साथ मारपीट कर लूटपाट व अपहरण की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने दोनों को अगवा कर एक कमरे में बंद कर जान से मारने की धमकी दी और फिरोती की मांग की। पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार अरूप दास निवासी नारायणपुरा बालिसखाना (उत्तर पश्चिम बंगाल) मछली व्यवसायी है। वह व्यवसायिक कार्य से अम्बिकापुर आया था और मानस होटल में ठहरा हुआ था। 3 फरवरी को वह अपने एक साथी के साथ मौलवी बांध तालाब मछली देखने जा रहा था। इसी दौरान स्कूटी और बाइक में सवार चार युवकों ने उन्हें रोककर पृच्छाछ की और गाली-गुलज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।



बदमाशों ने दोनों से 35 हजार रुपए, मोबाइल और पर्स लूट लिया।

अज्ञात स्थान पर ले जाकर मांगे दो लाख रुपए : इसके बाद बदमाशों दोनों को जबरन गाड़ी में बैठाकर एक अज्ञात स्थान पर ले गए, जहाँ उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपए की मांग की। डर और धमकियों के बीच बदमाशों ने दोनों

व्यवसायियों से अलग-अलग तरीकों से कुल 1 लाख 1 हजार रुपए और लूट लिए। अगले दिन सुबह बदमाशों ने दोनों को छोड़ दिया। इसके बाद पीड़ित अरूप दास ने कोतवाली थाना पहुँचकर घटना की सूचना दी।

डीआईजी के निर्देश पर गठित हुई टीम : घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी राजेश अग्रवाल ने कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम

गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम ने दो संदेहियों की पहचान कर हिरासत में लिया। पृच्छाछ में उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया।

दो आरोपी गिरफ्तार, रकम खाते में जमा की थी

पुलिस ने आरोपी अलताब खान (21 वर्ष) निवासी ग्राम जराहाडिह, चौकी रघुनाथपुर तथा शरद चौधरी (22 वर्ष) निवासी दरीपारा थाना मणिपुर को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ धारा 296, 351(3), 115(2), 190, 191(2), 127(7), 310(2), 135 बीएनएस के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है।

बैंक खाता कसता गया होल्ट

आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपने हिस्से की 56 हजार रुपए की रकम बैंक खाते में जमा कर दी थी। पुलिस से संबंधित खाते को होल्ट करा दिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल भी जब्त किए गए हैं।

कलेक्टर परिसर के हनुमान मंदिर में चोरी, दान पेटी से नकदी गायब



—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 05 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

शहर के कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। बुधवार रात करीब 4 बजे तीन नकाबपोश चोर मंदिर में घुसे और दान पेटी तोड़कर उसमें रखी नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार चोरों ने दान पेटी के पास लगे ग्रेनाइट को हटाकर लॉक खोला और रुपये निकाल लिए। करीब 15 मिनट के भीतर वे वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष गिरिश गुप्ता के अनुसार दान पेटी हर महीने खोली जाती है। कुछ दिन पहले ही पेटी खोली गई थी, इसलिए इसमें तीन से चार हजार रुपये होने का अनुमान है। पुलिस के अनुसार चोरी से पहले चोरों ने सिविल डिपार्टमेंट के पीछे संचालित एक पान उठे में भी वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है।

आवश्यकता के अनुसार बैंक से नहीं मिल रहे रुपए, आक्रोशित किसानों ने किया चक्काजाम



—संवाददाता—

अम्बिकापुर, 05 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

धान बेचने के बाद भी किसानों को समय पर पूरा भुगतान नहीं मिलने से नाराज किसानों ने गुरुवार को आकाशवाणी चौक स्थित सहकारी बैंक के बाहर चक्काजाम कर दिया। किसानों का कहना है कि वे कई दिनों से बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बार में सिर्फ 20-20 हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं। किसानों ने बताया कि बैंक में सुबह से लंबी कतार लग रही है। घंटों इंतजार के बाद भी पूरा भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि वर्तमान में शादी का सीजन चल रहा है। बेटे-बेटियों के विवाह सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए रुपयों की आवश्यकता है, लेकिन भुगतान में देरी के कारण परेशानी बढ़ गई है। बैंक के भीतर और सड़क पर किसानों की भीड़ बढ़ने पर स्थिति संभालने के लिए पुलिस जवान मौके पर पहुंचे।

13, 14 एवं 15 फरवरी को मैनपाट में होगा तीन दिवसीय भव्य आयोजन कलेक्टर अजीत वसंत ने तैयारियों के सम्बंध में अधिकारियों की ली बैठक

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 05 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

आगामी 13, 14 एवं 15 फरवरी को मैनपाट में रोपाखार जलाशय के समीप प्रस्तावित तीन दिवसीय 'मैनपाट महोत्सव 2026' की तैयारियों की समीक्षा हेतु कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक ली।

बैठक में महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विभागीय स्टॉल, मेले की व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों हेतु व्यवस्था, आमंत्रित एवं स्थानीय कलाकारों हेतु समुचित व्यवस्था, मंचोय व्यवस्था, बैठक व्यवस्था सहित



अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि पूरे आयोजन में कड़ी कानून व्यवस्था रहे। विभिन्न स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनाए जाएं, वाहनों की जांच के साथ हेल्मेट अनिवार्य हो। उन्होंने आमंत्रण पत्र, वाहन कार्यक्रम को सफल बनाने सभी तैयारियों, निर्माण, मुख्य मार्गों एवं कार्यक्रम स्थल में

ब्रांडिंग आदि की जानकारी ली। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा कि एनसीसी एवं एनएसएस के विद्यार्थियों को कार्यक्रम स्थल में वॉलेंटियर के रूप में दायित्व सौंपे जाएं। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने सभी तैयारियों किए जाने निर्देशित किया। बैठक में

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमोलक सिंह डिल्लो, जिला पंचायत सीईओ श्री विनय अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अमृत लाल धुव, नगर निगम आयुक्त श्री डी.एन. कश्यप सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व : मैनपाट महोत्सव की आवश्यक तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा श्री विनय कुमार अग्रवाल एवं सहायक नोडल अधिकारी आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. ललित शुक्ला एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) सीतापुर श्री रामसिंह ठाकुर होंगे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश सिंह डिल्लो, जिला पंचायत सीईओ श्री विनय अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अमृत लाल धुव, नगर निगम आयुक्त श्री डी.एन. कश्यप सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

इसी प्रकार मंचोय व्यवस्था, आमंत्रण कार्ड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बैठक व्यवस्था, आवागमन एवं सत्कार, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा, विभागीय स्टॉल, साज-सज्जा, प्रोटोकॉल व्यवस्था, रैस्ट हाउस एवं सर्किट हाउस, हेलीपैड की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

विद्युत वितरण केंद्रों में समारोह आयोजित, उपभोक्ता सम्मानित

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 05 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा रजत जयंती वर्ष 2025-26 के उपलक्ष्य में सरगुजा संभाग के अंतर्गत विभिन्न वितरण केंद्रों में 2 से 4 फरवरी तक समारोह आयोजित किया गया। सरगवां, लटीरी, राजपुर, दरिमा, कुन्नी, धौरपुर, अम्बिकापुर (ग्रामीण), लखनपुर, लुण्डा, लमगांव, पेटला एवं सीतापुर में आयोजित इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता एवं ग्रामीणजन शामिल हुए। समारोहों में विद्युत व्यवस्था की भूमिका, उपभोक्ताओं के योगदान तथा शासन स्तर पर संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विशेष रूप से पी.एम.



कुसुम योजना एवं पी.एम. सूर्य घर योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सम्मानित भी किया गया। बीपीएल श्रेणी के ऐसे पाँच उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने निर्धारित यूनिट के

अनुरूप विद्युत खपत की। इसके अलावा पाँच घरेलू उपभोक्ताओं को, जिन्होंने पिछले दो वर्षों से नियमित रूप से बिना बकाया के बिजली बिल का भुगतान किया, प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कृषक जीवन ज्योति योजना के पाँच हिताग्रहियों तथा पीएम सूर्य घर योजना के पाँच लाभार्थियों को भी लक्की ड्रा के माध्यम से सम्मानित किया गया। समारोहों में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। उपस्थित अतिथियों ने विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार, ऊर्जा संरक्षण और उपभोक्ता सहयोग की सराहना की। कार्यक्रमों में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों का सक्रिय सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

सहायक ग्रेड-03 (सविदा) के 02 पद हेतु 07 फरवरी को होगी कौशल परीक्षा

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 05 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

जिला खनिज संस्थान न्यास सरगुजा अंतर्गत सहायक ग्रेड-03 (सविदा) के 02 पदों हेतु अहर्ताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया था। उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत लिखित परीक्षा 03 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में पात्र 38 अभ्यर्थियों में से 10 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे तथा शेष 28 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में

प्रतिभागीता की गई। प्रतिभागी 28 अभ्यर्थियों में से 15 अभ्यर्थी उत्तीर्ण तथा 13 अनुत्तीर्ण पाए गए। जिसका प्रकाशन जिले के वेबसाइट www.surguja.nic.in एवं कार्यालय के सूचना पटल में किया गया है। जिले के अपर कलेक्टर ने बताया लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी के पर्यवेक्षण में 07 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे लाईवलीट्टड कॉलेज गांधी चौक अम्बिकापुर में किया गया है।

लिखित परीक्षा में केवल उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो सकेंगे। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। कौशल परीक्षा में अवधि 30 मिनट होगा, कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित अंक 30 है। परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश : अभ्यर्थी अपने साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/प्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या अन्य कोई ऐसी वस्तु जिसमें परीक्षा हेतु व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, साथ में रखना वर्जित रहेगा। परीक्षार्थी निर्धारित समय से आधा घण्टा पूर्व परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु जिले के वेबसाइट www.surguja.nic.in का निरंतर अवलोकन करते रहें, अन्य किसी माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचना नहीं दी जाएगी।

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्वक पहल असोला मिडिल स्कूल में दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजित, 23 हिताग्रहियों को सहायक उपकरण वितरित

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 05 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

आज ग्राम पंचायत असोला स्थित मिडिल स्कूल परिसर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जिला पंचायत सदस्य दिव्या सिंह सिसोदिया की पहल पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 23 निशक्तजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शिविर के दौरान दिव्यांगजनों को 13 ट्राई-साइकिल, 3 व्हीलचेयर, 2 श्रवण यंत्र, 3 स्तर छड़ी, 2 बैसाखी तथा कुत्रिम अंग का वितरण किया गया। इसके साथ ही क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से दिव्यांगजनों की सूची संकलित कर उन्हें आगे भी सहायता उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभागों को जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि भारत सिंह सिसोदिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस प्रकार के शिविर उनके जीवन में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और



आत्मनिर्भरता लाने का कार्य करते हैं। भाजपा की सोच हमेशा से अंत्योदय की रही है, और भाजपा की साथ सरकार हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ' जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 02 की सदस्य दिव्या सिंह सिसोदिया ने कहा कि दिव्यांगजनों को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि अवसर और संसाधन की आवश्यकता होती है। इस शिविर के माध्यम से उनका दैनिक जीवन सरल बनाने का प्रयास किया गया है। भविष्य में भी क्षेत्र के सभी पात्र दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान जनता उपाध्यक्ष सतीश यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष जायसवाल, क्षेत्र के सरपंच-सचिव, भाजपा कार्यकर्ता तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

धन्यवाद की तस्वीरें या श्रेय की तैयारी? बैकुंठपुर अस्पताल पर राजनीति का 'सेल्फी मोमेंट'

धन्यवाद के बहाने श्रेय की राजनीति? बैकुंठपुर अस्पताल पर फोटो बनाम हकीकत

- अस्पताल अधूरा... श्रेय पूरा ! बैकुंठपुर में आभार की आड़ में सियासी संदेश
- धन्यवाद या दावा ? 23 करोड़ की स्वीकृति के बाद शुरू हुई श्रेय की दौड़
- ईंट किसकी,फोटो किसका ? अस्पताल निर्माण पर सियासी 'सेल्फी' युद्ध
- आभार की पोस्ट या क्रेडिट की कोशिश ? बैकुंठपुर में अस्पताल से ज्यादा चर्चा तस्वीरों की
- अस्पताल से पहले श्रेय का उद्घाटन! बैकुंठपुर की राजनीति पर व्यंग्य...



बैकुंठपुर, 05 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।
कोरिया जिले में लंबे समय से अधूरे पड़े 200 बिस्तर वाले जिला चिकित्सालय के निर्माण को आखिरकार नई रफ्तार मिलने का रही है, छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 23 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद जहां जिलेवासियों में खुशी का माहौल है, वहीं इस स्वीकृति के बाद शुरू हुई राजनीतिक हलचल और श्रेय की चर्चा भी अब खुलकर सामने आने लगी है, खासकर बैकुंठपुर की पूर्व विधायक द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए आभार पोस्ट ने इस मुद्दे को नया राजनीतिक रंग दे दिया है, लेकिन जैसे ही निर्माण की राह साफ हुई, बैकुंठपुर की राजनीति में एक पुराना खेल फिर से शुरू हो गया - धन्यवाद भी हमारा... और श्रेय भी हमारा। बता दें की अस्पताल की इमारत अभी पूरी तरह खड़ी भी नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया की दीवारों पर राजनीतिक तस्वीरें जरूर खड़ी हो गईं, पूर्व विधायक का आभार पोस्ट सामने आया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक को धन्यवाद दिया गया। पर उसी पोस्ट में अपने कार्यकाल की यादें और पुरानी तस्वीरें भी

शामिल थीं, अब जनता पूछ रही है - यह कृतज्ञता है या 'क्रेडिट कार्ड' का बिल पहले से भरने की कोशिश? सियासत का यह पुराना नियम है कि काम चाहे किसी का भी हो, फोटों में सबको जगह चाहिए, फर्क बस इतना है कि पहले मंच पर माला पहनाई जाती थी, अब टाइमलाइन पर पोस्ट सजाई जाती है, व्यंग्य यह है कि अस्पताल का निर्माण वर्षों तक फाइलों में सोता रहा, लेकिन जैसे ही स्वीकृति आई, राजनीति जाग गई, सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर यह परियोजना इतनी ही महत्वपूर्ण थी, तो पहले इसे डीएमएफ के भरोसे क्यों छोड़ा गया? क्या तब नीति सही थी और अब गलत है, या फिर हर दौर में नीति वही सही होती है जिसमें राजनीतिक फायदा ज्यादा दिखे? जानकारों का कहना है कि अगर शुरुआत से ही स्वास्थ्य विभाग की सीधी स्वीकृति ली जाती, तो शायद आज मरीजों को जमीन पर लेटकर इलाज नहीं कराना पड़ता, जिले की जनता के लिए अस्पताल कोई राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत है, लेकिन यहां चर्चा इलाज से ज्यादा इमेज की हो रही है। एक तरफ सरकार के समर्थक इसे वर्तमान नेतृत्व की उपलब्धि बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष यह याद दिलाने में लगा है कि नींव उनके समय में रखी गई थी, जनता के बीच अब नया व्यंग्य चल

अधूरा सपना, अब पूरी होने की उम्मीद
जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर का नया भवन वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था, इस परियोजना की शुरुआत पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में हुई थी, लेकिन पर्याप्त और नियमित फंडिंग के अभाव में निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया, बताया जाता है कि निर्माण के लिए डीएमएफ (जिला खनिज न्यास निधि) मद पर निर्भर रहने की रणनीति अपनाई गई थी, जिसके कारण समय पर पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो सकी और अस्पताल का ढांचा अधूरा रह गया, अब वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग ने सीधे प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए 23 करोड़ से अधिक राशि मंजूर की है, इससे निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जिले को आधुनिक सुविधाओं वाला 200 बिस्तरों का अस्पताल मिल सकेगा।

मरीजों की परेशानी बनी थी बड़ी वजह
अस्पताल निर्माण में देरी का खामियाजा जिले के हजारों मरीजों को भुगतना पड़ा, पुराने जिला चिकित्सालय में सीमित बिस्तरों के कारण कई मरीजों को जमीन पर लेटकर इलाज करवाने की मजबूरी रही, जबकि गंभीर मरीजों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था, ऐसे में नई स्वीकृति को स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह भवन समय पर पूरा हो जाता तो जिले की स्वास्थ्य तस्वीर काफी पहले बदल चुकी होती।

पड़ा है - 'ईंट किसने रखी और छत किसने खली, इसका हिसाब तो नेता करेंगे... मरीजों को बस बिस्तर चाहिए।'
विपक्ष ने भी जताया आभार, पूर्व विधायक का पोस्ट चर्चा में : प्रशासकीय स्वीकृति के बाद जहां आम नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने स्वास्थ्य मंत्री और सरकार को धन्यवाद दिया, वहीं जिले का विपक्ष भी खुलकर आभार जताता नजर आया, इसी बीच बैकुंठपुर की पूर्व विधायक द्वारा किया गया सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बन गया, उन्होंने अपने पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक को धन्यवाद देते हुए अपने कार्यकाल में अस्पताल निर्माण की शुरुआत का भी उल्लेख किया और कुछ पुरानी तस्वीरें साझा कीं।

आभार या श्रेय? लोगों के बीच उठे सवाल
पूर्व विधायक के पोस्ट के बाद जिले में यह बहस तेज हो गई है कि यह केवल कृतज्ञता ज्ञापन है या फिर अपने हिस्से का श्रेय याद दिलाने की कोशिश, कई लोग इसे राजनीतिक परंपरा का हिस्सा मानते हुए कहते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स में हर नेता अपनी भूमिका दिखाना चाहता है, जबकि कुछ लोग इसे श्रेय की होड़ बताते हुए तज कस रहे हैं - 'अस्पताल अभी बना नहीं, लेकिन श्रेय की राजनीति पहले से तैयार है।'
डीएमएफ मॉडल पर भी उठे सवाल
जानकारों का मानना है कि शुरुआत में डीएमएफ मद पर निर्भर रहने के बजाय यदि सीधे स्वास्थ्य विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति ली जाती, तो निर्माण कार्य वर्षों पहले पूरा हो सकता था, अब विभागीय स्तर से मिली स्वीकृति को प्रशासनिक दृष्टि से सही कदम माना जा रहा है, जिससे फंडिंग में स्पष्टता आएगी और निर्माण की गति बढ़ेगी।

राजनीति से परे जनता की उम्मीद
हालांकि श्रेय और आभार की राजनीति अपनी जगह जारी है, लेकिन आम लोगों की प्राथमिकता सिर्फ इतनी है कि अस्पताल जल्द से जल्द बनकर तैयार हो और जिले को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, जिले के वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि अस्पताल किसी एक सरकार या नेता का नहीं, बल्कि पूरे समाज की जरूरत है, इसलिए राजनीतिक बहस से ज्यादा ध्यान निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय-सीमा पर होना चाहिए।

आगे क्या?
अब सबकी नजर इस बात पर है कि स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और कब तक यह बहुमती 200 बिस्तर वाला जिला चिकित्सालय पूरी तरह तैयार होकर जनता की सेवा में समर्पित होता है, अगर काम समय पर पूरा होता है तो यह परियोजना कोरिया जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।

14 साल बाद 67 सब-इंजीनियर बाहर..हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी... 'बैकडोर एंट्री नहीं चलेगी', सिस्टम की गलती का बोझ कर्मचारियों पर

बिलासपुर, 05 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वर्ष 2011 की विवादित भर्ती पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 67 सब-इंजीनियर (सिविल) की नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया है, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों और योग्यता मापदंडों में बदलाव करना कानून के खिलाफ है और 'बैकडोर एंट्री' किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती, कोर्ट ने माना कि विज्ञापन में तय अंतिम तिथि तक आवश्यक डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है, चयन की तारीख को आधार नहीं बनाया जा सकता। जांच में सामने आया कि 2011 की भर्ती प्रक्रिया में 89 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला एक कड़ा संदेश है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों से समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन यह मामला शासन की देरी, लापरवाही और जवाबदेही की कमी को भी उजागर करता है, कानून ने अपना काम कर दिया, अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या सिस्टम की गलती के असली जिम्मेदारों पर भी कभी कार्रवाई होगी या नहीं।

दो को राहत, बाकी की नियुक्ति खत्म
डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी क्रमांक 4 से 73 तक की नियुक्तियां निरस्त कर दीं। हालांकि वर्षा दूबे और अभिषेक भारद्वाज को राहत दी गई क्योंकि उन्होंने कट-ऑफ तिथि से पहले आवश्यक योग्यता पूरी कर ली थी, मानवीय आधार पर कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अब तक दिए गए वेतन और भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी।

सरकारी लापरवाही पर तीखी टिप्पणी
कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और नियमों के उल्लंघन को गंभीर चूक बताया, फैसले में कहा गया कि प्रशासनिक गलतियों के कारण कई अभ्यर्थी अब सही उम्र में पहुंच गए हैं जहां दूसरी सरकारी नौकरियों के अवसर लगभग खत्म हो चुके हैं।

एफआईआर और जांच का लंबा इतिहास
भर्ती गड़बड़ी को लेकर 2022 में रायपुर के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी, आरोप था कि निर्धारित पदों से ज्यादा नियुक्तियों की गईं और कई अभ्यर्थी कट-ऑफ तिथि के बाद योग्य घोषित किए गए, सरकार द्वारा गठित तीन समितियों ने भी 89 नियुक्तियों को अवैध माना था, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

क्या था पूरा मामला?
ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के तहत वर्ष 2011 में 275 सब-इंजीनियर पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन आरोप है कि नियमों में बदलाव कर 275 की जगह 383 नियुक्तियां कर दी गईं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की थी जिनकी योग्यता कट-ऑफ तिथि तक पूरी नहीं हुई थी, इस भर्ती को चुनौती देते हुए रवि तिवाड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पहले सिविल बेंच ने राहत देने से इनकार किया, लेकिन डिवीजन बेंच में अपील के बाद पूरी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल खड़े हुए और अंततः नियुक्तियां रद्द कर दी गईं।

शासन का तर्क और कोर्ट की सख्ती
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे अभ्यर्थियों को मौका देने का बाद में निर्णय लिया गया था और कई कर्मचारी 14 साल से सेवा दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा कि लंबी सेवा अवधि किसी अवैध

व्यवस्था की भूल, युवाओं की धूल-आखिर जिम्मेदार कौन?
यह फैसला कानून की नजर में भले ही सही हो, लेकिन शासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा गया है, 14 साल तक सेवा लेने के बाद अचानक नौकरी खत्म होना केवल कानूनी मसला नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय संकट भी है।

14 साल का भरतेश या प्रशासनिक भ्रम?
इन सब-इंजीनियरों ने अपने जीवन का अहम दौर सरकारी सेवा में बिताया। यदि नियुक्तियों नियमों के खिलाफ थीं, तो शासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या यह लापरवाही थी या जिम्मेदारी से बचने की कोशिश?
नियम बदलने वाले सुरक्षित, नौकरी करने वाले बाहर
नियमों में फेरबदल और पदों की संख्या बढ़ाने का निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया, लेकिन सजा उन अभ्यर्थियों को मिली जिन्होंने केवल आवेदन किया था। सवाल उठता है कि भर्ती प्रक्रिया को 'अवैध' बनाने वाले अधिकारी और निर्णयकर्ता कब जवाबदेह होंगे?
समितियों की रिपोर्ट पर चुप्पी क्यों?
तीन समितियों की नकारात्मक रिपोर्टों के बावजूद वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं होना बताता है कि सिस्टम में कहां न कहां राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव रहा। अब जब फैसला आया, तो इसकी कीमत 67 परिवारों को चुकानी पड़ रही है।

रजत जयंती वर्ष पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा संगमागस्तरीय समारोह का हुआ आयोजन

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी....
विद्युत विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही पी.एम. सूर्य घर योजना के बारे में लोगों विस्तारपूर्वक बताया गया तथा योजना का लाभ लेने प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान बी.पी.एल. श्रेणी के पांच उपभोक्ता जिन्होंने पिछले 2 वर्षों से निर्धारित यूनिट का खपत किया हो, घरेलू 5 उपभोक्ताओं को जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में बिना पिछली बकाया राशि के नियमित रूप से विद्युत देयक का भुगतान किया हो, कृषक जीवन ज्योति के पांच उपभोक्ता एवं पी.एम. सूर्य घर योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं में से पांच लाभार्थी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 6 को परीक्षा पे चर्चा

अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों, विकासखण्ड मुख्यालय तथा जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न सोशल मीडिया (यूट्यूब, फेसबुक लाइव), दूरदर्शन, PM eVidya TV, रेडियो चैनलों और विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि पर किया जाएगा।

मगरमच्छ वाला घोटाला, कछुए वाली जांच

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में नियम छुटी पर, माफिया ड्यूटी पर!

» निलंबन आदेश 'अंडरग्राउंड', एआई कैमरा 'ऑन पेपर', जिम्मेदार 'ऑफ मोड' - सवाल के बोझ तले पूरा सिस्टम

» शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में सख्त कभी फेल, एआई कैमरा भी मौन!

» निलंबन आदेश दवा, स्टैकिंग नियम गायब, एआई रिपोर्ट में Quantity Difference- फिटर भी फाइल में सब 'Resolved'

» शिवप्रसादनगर धान खरीदी में सख्त कफेल, AI कैमरा भी 'Resolved'!

» निलंबन छुपा, स्टैकिंग

गड़बड़, AI रिपोर्ट में फर्क-फिर भी सिस्टम बोले सब ठीक!

» AI ने पकड़ा खेल, फाइलों ने किया 'Resolved'- शिवप्रसादनगर धान खरीदी पर बड़े सवाल

» धान खरीदी या मैनेजमेंट मॉडल? SOP गायब, कैमरा खामोश, जिम्मेदार मौन

» 350 क्विंटल का गणित विगड़, 875 बोरी का सवाल- शिवप्रसादनगर में जांच की धीमी चाल

» आदेश कागजों में, खेल मैदान में- शिवप्रसादनगर धान खरीदी बना सिस्टम की परीक्षा

» 350 क्विंटल की गाड़ी और 875 बोरी का गणित

4 जनवरी की एआई रिपोर्ट ने तो पूरा गणित ही बिगाड़ दिया, रिपोर्ट के अनुसार 350 क्विंटल धान ले जाने वाली गाड़ी में करीब 875 बोरी होनी चाहिए थी, मगर कैमरा विश्लेषण ने संदेह जताया, भौतिक सत्यापन की सिफारिश भी हुई, पर जांच का हाल ऐसा है जैसे फाइलों योगा कर रही हों- एक जगह स्थिर।

» राइस मिलार का नाम और दबाव की फुसफुसाहट

महामया राइस मिल और उसके संचालक मनोज का नाम भी चर्चाओं में तैर रहा है, आरोप है कि ऊपर तक दबाव बनाकर मामलों को ठंडा रखने की कोशिश हो रही है, हालांकि आधिकारिक पृष्ठ अभी तक सामने नहीं आई है- यानी कहानी अभी सूत्रों के हवाले से ही चल रही है।

» रात का खेल और कैमरों की खामोशी

स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय बारदाना बाहर ले जाने की चर्चाएं भी होती रही हैं, आरोप यह भी है कि कैमरों की निगरानी समिति के पास नहीं बल्कि बाहरी कार्यालय के पास है, अगर यह सही है तो पारदर्शिता का उद्देश्य ही उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि कैमरा दिखेगा जरूर, मगर नियंत्रण कहीं और होगा।

-अंकार पाण्डेय-

सूरजपुर, 05 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र इन दिनों सिर्फ धान की तौल के लिए नहीं बल्कि सवालों के वजन के लिए भी चर्चा में है, आरोपों की परतें इतनी मोटी हैं कि अगर आधी भी सही साबित हुई तो यह मामला साधारण लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, दिलचस्प बात यह है कि जहां घोटाले का आकार मगरमच्छ जैसा बताया जा रहा है, वहीं जांच की रफ्तार कछुए से भी धीमी नजर आ रही है।

बता दे कि शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र का यह प्रकरण सिर्फ एक केंद्र की कहानी नहीं, बल्कि उस भरोसे की परीक्षा है जो किसान और जनता प्रशासन से रखते हैं, तकनीक, आदेश और नियम तभी मायने रखते हैं जब उन्हें लागू करने की इच्छा भी उनकी ही मजबूत हो, वरना मगरमच्छ के आकार के आरोपों के बीच कछुए की चाल वाली जांच जनता के मन में यही सवाल छोड़ जाती है- क्या सच में कोई सुन रहा है, या सिर्फ फाइलों में हरे रंग का टिक लगाकर सब कुछ ठीक मान लिया गया है?

धान में खेल, सिस्टम फेल!

मगरमच्छ का घोटाला, कछुए की जांच!

शिवप्रसादनगर धान खरीदी में SOP गायब, AI कैमरा अलर्ट भी 'Resolved'

निलंबन आदेश छुपा, अलग स्टैकिंग नहीं — 350 क्विंटल के नाम पर बड़ा खेल? — AI रिपोर्ट में 'Quantity Difference' से हड़कंप

निलंबन आदेश छुपा, अलग स्टैकिंग नहीं — 350 क्विंटल के नाम पर बड़ा खेल? AI रिपोर्ट में 'Quantity Difference' से हड़कंप

आदेश कागजों में, खेल मैदान में — सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम

जांच करें: 350 क्विंटल का... फोटो में 875 बोरी क्यों कम? जांच या सिर्फ सिस्टम का मैनेजमेंट!

दामाद संस्कृति या प्रशासनिक संरक्षण?

शिवप्रसादनगर मामला आग की तरह फैलता सवाल

CCTV में दिखा: शिवप्रसादनगर में घोटाले की रात निकले 6000 बरदाना

सबसे बड़े सवाल

» निलंबन आदेश सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ?

» एसओपी का पालन किसने रोका और क्यों?

» एआई कैमरा अलर्ट के बाद वास्तविक जांच हुई या नहीं?

» Resolved का मतलब सम्पन्न है वा सिर्फ सिस्टम की औपचारिकता?

राइस मिल का नाम और दबाव की चर्चा

एआई रिपोर्ट में महामया राइस प्रोडक्ट्स का नाम आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, सूत्रों का दावा है कि मिलर स्तर से दबाव बनाकर जांच को धीमा करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि आधिकारिक पृष्ठ अभी नहीं हुई है, लेकिन चुपचाप ने संदेह को और गहरा कर दिया है, अगर आरोप सत्य हैं तो प्रशासन को तुरंत स्पष्ट बयान देना चाहिए, और अगर सही हैं तो कार्रवाई में देरी खुद एक सवाल बन जाती है।

» व्यंग्य का सच: सिस्टम या सर्कस? <<

पूरा मामला देखकर लोगों के बीच तंज चल रहा है- यहाँ धान कम और कहानी ज्यादा तौली जा रही है, एसओपी मौजूद है, कैमरा मौजूद है, रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन जवाबदेही कहीं नजर नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे हर स्तर पर कोई न कोई रिजल्ट बटन दबाकर आगे बढ़ जाता है, मगर जमीन पर समस्या वहीं खड़ी रहती है।

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में धान नहीं... घोटाला तोला गया?

धान खरीदी घोटाले की जांच के घेरे में शिवप्रसादनगर समिति से जुड़े चे नाम

सूरी शीत, सुनी टैकर, कछुए की ड्यूटी के अड्डे

कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है

कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है

निलंबन आदेश: कागज पर कार्रवाई, मैदान में पुरानी व्यवस्था

जानकारी के अनुसार 23 जनवरी को केंद्र प्रभारी साधना कुशवाहा को निलंबित किया गया, लेकिन आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ, निलंबन की खबर बाजार में घूमती रही, पर आधिकारिक दस्तावेज जैसे किसी अलमारी में बंद रहे, आरोप है कि निलंबित होने के बाद भी 30 जनवरी तक खरीदी में उनके हस्ताक्षर चलते रहे, बीच में चार दिन के लिए नए प्रभारी के रूप में मन्नू लाल को नियुक्ति हुई, मगर यहाँ भी सवाल उठे की क्या जिम्मेदारी नियम से दी गई या नेटवर्क से तय हुई? स्थानीय चर्चाओं में दोनों नामों का पुराने विवादों से जुड़ना भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रहा है, प्रशासन भले चुप हो, मगर जनता पूछ रही है कि क्या यही विकल्प बचे थे?

निलंबन भी 'सीक्रेट मिशन' जैसा!

23 जनवरी को प्रभारी साधना कुशवाहा के निलंबन की खबर आई, मगर आदेश ऐसे गायब रहा जैसे सरकारी फाइलों में ईमानदारी, सवाल यह है कि जब प्रभारी निलंबित थीं तो 30 जनवरी तक धान खरीदी में उनके हस्ताक्षर कैसे चलते रहे? यहाँ तो हल ऐसा दिखा मानो सिस्टम कह रहा हो- निलंबन कागज पर, काम मैदान पर। चार दिन के लिए बनाए गए नए प्रभारी मन्नू लाल भी वही निकले जिनका नाम पुराने विवादों में गूँज चुका है। जनता पूछ रही है- क्या यहाँ प्रभारी चयन योग्यता से होता है या पुराने 'अनुभव' से?

एसओपी का हाल: आदेश जारी, पालन गायब

धान खरीदी के अंतिम चरण में शासन ने स्पष्ट एसओपी जारी किया था- 23 जनवरी तक भौतिक सत्यापन, पंचनामा, फोटोग्राफी और क्रॉस वेरिफिकेशन अनिवार्य था, 27 जनवरी से नई स्टैकिंग अलग रखनी थी और परिवहन भी सत्यापित स्टॉक से ही होना था, लेकिन आरोप है कि शिवप्रसादनगर में एसओपी सिर्फ पोस्टर तक सीमित रहा, अलग स्टैकिंग नहीं हुई, पुराने और नए स्टॉक का मिश्रण बना रहा और परिवहन भी बिना पारदर्शी सत्यापन के चलता रहा, व्यंग्य यह है कि नियम इतने साफ थे कि समझने की जरूरत नहीं थी, फिर भी पालन नहीं हुआ, यानी या तो आदेश को हल्के में लिया गया या फिर किसी ने जानबूझकर आंखें मूंद लीं।

एआई कैमरा: तकनीक जागी, जिम्मेदारी सोई?

सरकार ने धान खरीदी में पारदर्शिता के लिए एआई कैमरे लगाए थे ताकि हर गतिविधि पर नजर रहे, 4 जनवरी 2026 को एआई रिपोर्ट में दर्ज है कि शिवप्रसादनगर से 350 क्विंटल धान लेकर एक गाड़ी महामया राइस प्रोडक्ट्स गई, लेकिन फोटो एनालिसिस में संदेह जताया गया कि गाड़ी में लगभग 875 बोरी धान होना चाहिए था, जो नजर नहीं आया, सिस्टम ने साफ लिखा- Quantity Difference, और उपार्जन केंद्र व मिल का भौतिक सत्यापन करने की सिफारिश भी की, यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, रिपोर्ट में मामला बाद में Resolved दिखाया गया, अब सवाल है- क्या जांच सच में हुई या सिर्फ स्क्रीन पर हरे रंग का टिक लगाकर फाइल बंद कर दी गई? अगर PV हुआ तो उसका सार्वजनिक रिकॉर्ड कहाँ है?

सूरजपुर से विशेष व्यंग्यात्मक रिपोर्ट

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र इन दिनों प्रशासनिक पारदर्शिता का नहीं बल्कि व्यवस्था अभाव का मॉडल बन चुका है, यहाँ नियम-कायदे ऐसे गायब हैं जैसे बैकड में चाय खत्म होते ही नेता गायब हो जाते हैं, आरोप है कि घोटाला मगरमच्छ के आकार का है, लेकिन जांच कछुए की चाल से भी धीमी चल रही है- शायद इसलिए ताकि सच मजिल तक पहुँचते-पहुँचते थक जाए।

माफिया राज का 'लोकल मैनेजमेंट मॉडल'

स्थानीय चर्चाओं में कहा जा रहा है कि इस केंद्र में कौन प्रभारी बनेगा, यह फाइल नहीं बल्कि 'नेटवर्क' तय करता है, रात के अंधेरे में बारदाना बाहर निकलने की बातें हो रही हैं और कैमरे भी कथित तौर पर उतरे ही सकिंग हैं जितनी चुनाव के बाद जनता की समस्याएं।

एआई कैमरा: तकनीक हाईटेक, नतीजा लो वॉल्टेज

सरकार ने पारदर्शिता के लिए एआई कैमरे लगाए, लेकिन यहाँ सवाल यह उठ रहा है कि कैमरे लगे हैं या सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए लगाए गए हैं? बताया जा रहा है कि कैमरों की कमान समिति के बजाय बाहर किसी कार्यालय के पास है- यानी निगरानी भी 'आउटसोर्स'।

अवैध कब्जाधारियों पर चला नगर निगम का बुलडोज़र

-संवाददाता- कोरबा, 05 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

कोरबा जिले में अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर विघ्न डालने वालों से नगर निगम की अतिक्रमण निरोधी उडनदस्ता टीम सख्ती के साथ निपट रही है। इसी कड़ी में ढोढ़ीपारा क्षेत्र अंतर्गत अतिक्रमण हटाने के दौरान निगम कर्मचारियों के साथ अभद्रता व हुडडंग करने वाली अतिक्रमणकारी महिला को महिला सुरक्षा बल ने सख्ती के साथ काबू में किया तथा कड़ी हिदायत दी कि यदि कार्यवाही के दौरान दोबारा विघ्न पैदा किया जाता है तो अतिक्रमण तो हटेगा ही, साथ ही वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय भूमियों, निगम की जमीनों व सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने निगम में एक सख्त अतिक्रमण निरोधी उडनदस्ता टीम का गठन कर क्षेत्र में किए जा रहे अवैध कब्जों व अतिक्रमण को हटाने की कमान निगम के उपायुक्त नीरज कौशिक को दी



अब निगम की टीम ऐसे लोगों से सख्ती से निपट रही है। निगम की उडनदस्ता टीम के साथ पुरुष सुरक्षा बल के साथ महिला सुरक्षा बल भी तैनात रखी जा रही है, जो कार्यवाही में विघ्न-बाधा पैदा करने वाली महिला सदस्यों को भी सख्ती के साथ काबू में करने का कार्य करती है। जानकारी के अनुसार सीएसईबी-वीर मुख् मार्ग पर स्थित ढोढ़ीपारा बस्ती में निगम का बुलडोजर चला। ढोढ़ीपारा बस्ती में स्थित उपस्वास्थ्य केन्द्र के बगल के घर में, घर के सामने बीम कालम खड़ाकर व छुजे का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए निगम के अतिक्रमण निरोधी उडनदस्ता की टीम ने कार्यवाही करते हुए उक्त अतिक्रमण को तोड़ा। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण करने वाली महिला ने टीम के सदस्यों के साथ अभद्रता की तथा हुडडंग करते हुए कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास किया, जिस पर मौके में उपस्थित महिला सुरक्षा बलों ने सख्ती के साथ कार्यवाही करते हुए महिला को काबू में किया, साथ ही कड़ी हिदायत दी कि यदि दोबारा कार्यवाही में विघ्न उपस्थित किया जाता है तो अतिक्रमण तो निश्चित रूप से हटेगा ही, साथ ही वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर, 8090

ईश्वरहार

क्रमांक/1843/वाचक-2/2025
सूरजपुर दिनांक 22/01/2026

सर्व साधारण ग्रामवासी केशवनगर प0800...तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेक सुभारो बार्ड पति स्व0 राम प्रसाद जति गोड़ निवासी ग्राम केशवनगर पोस्ट...थाना विश्रामपुर तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ090) ने अपने पति स्व0 राम प्रसाद पिता बोधन मूल्य तिथि 10/09/1999 स्थान केशवनगर के मूल्य पत्र हेतु आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस न्यायालय में जिस व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति/आक्षेप हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिभावक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 06/02/2026 दिन...को उपस्थित होकर दावा/आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति/आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

तहसीलदार सूरजपुर, छ090

नाम परिवर्तन

मैं सुरेश कुमार यादव आ. कुंवर राम उम्र 45 वर्ष निवासी म.नं- 301 वार्ड नं-17 कदमटोली घुघरी थाना व तह. बगीचा जिला जशपुर छ.ग. का है। जो कि मेरी पुत्री सोनल यादव का आधार कार्ड नं- 895178846174 है जिसमें उसका नाम त्रुटिवश प्रियल यादव दर्ज हो गया है। मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सोनल यादव है जो उसके समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में अंकित नाम प्रियल यादव को विलोपित कर सोनल यादव दर्ज किया जाये, जिसके संबंध में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

शपथकर्ता सुरेश कुमार यादव आ. कुंवर राम निवासी म.नं- 301 वार्ड नं-17 कदमटोली घुघरी थाना व तह. बगीचा जिला जशपुर छ.ग.

वनमण्डल बलरामपुर द्वितीय निविदा दिनांक 13.02.2026

निविदा द्वारा विक्रय हेतु रखी जाने वाली राजसात वाहनों का विवरण

क्र0	लाट	थप्पी क्र0	वाहन का प्रकार	वाहन का पंजीयन क्रमांक	वाहन का स्थिति है?
1	2	3	4	5	6
1	-	-	पिकअप	UP64D-8429	वन परिक्षेत्राधिकारी वाइडफनर निवास कैम्पस में खड़ा है।
2	-	-	महेन्द्रा पिकअप	CG15-A-2298	वन परिक्षेत्राधिकारी निवास कैम्पस रामानुजगंज में खड़ा है।
3	-	-	टाटा पिकअप	MM-950MD2KX-DX-62290	वन परिक्षेत्राधिकारी निवास रामानुजगंज में खड़ा है।
4	-	-	महेन्द्रा बोलेरो	CG15B-1846	वन परिक्षेत्राधिकारी बलरामपुर कैम्पस में खड़ा है।

वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर वनमण्डल- बलरामपुर

जी नंबर-252606463/3

माला, बैठक और महत्वाकांक्षा

क्या 25 लोगों ने तय कर दिया 25 हजार का भविष्य ?

25 हजार का समाज...और 25 लोगों का फैसला! कोरिया में प्रतिनिधित्व या राजनीतिक रिहर्सल ?

माला पहनते ही बन गए नेता ? साहू समाज में 'घोषणा राजनीति' पर बड़ा सवाल

प्रदेश आदेश ठंडे बस्ते में, कोरिया में अलग ही चल रहा 'संगठन मॉडल'

समाज सेवा या 2028 का टिकट प्लान ? साहू समाज की सियासत गरमाई

बैठक छोटी, दावा बड़ा-कौन तय करेगा 25 हजार की आवाज ?

प्रदेश से ऊपर कौन ? कोरिया में अध्यक्ष घोषणा पर उठे तीखे सवाल

मालाओं की राजनीति या समाज का नेतृत्व ? कोरिया में विवाद गरमाया

आज अध्यक्ष... कल टिकट ? साहू समाज में बढ़ती राजनीतिक सुगबुगाहट

घोषणा सभा या टिकट लॉन्चिंग ? साहू समाज की सियासत पर कटाक्ष

प्रदेश का पत्र हल्ला या महत्वाकांक्षा भारी ? कोरिया में उठे सवाल

माला, मंच और महत्वाकांक्षा-समाज की राजनीति का नया फार्मूला

जिसके पास माला ज्यादा... वही नेता ज्यादा ? साहू समाज में गरमा गई बहस

समाज का प्रतिनिधित्व या व्यक्तिगत बार्डिंग ? कोरिया में सियासी खींचतान

समाज की ताकत या कुछ चेहरों की चाहत ? कोरिया मॉडल पर सवाल



रवि सिंह- कोरिया, 05 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। कभी समाज सेवा और संगठनात्मक मजबूती के लिए पहचाना जाने वाला साहू समाज इन दिनों कोरिया जिले में एक नए तरह के प्रयोग से गुजरता दिखाई दे रहा है, यहाँ समाज का प्रतिनिधित्व अब जनसमर्थन से नहीं, बल्कि सीमित बैठक और मालाओं की संख्या से तय होता नजर आ रहा है, समाज यह है कि क्या सच में 25 हजार लोगों की आवाज सिर्फ 25 लोगों की बैठक में कैद हो सकती है, या फिर यह सब आने वाले विधानसभा

चुनाव 2028 की टिकट राजनीति का ट्रायल रन है? बता दे कि कोरिया जिले में साहू समाज का अध्यक्ष विवाद अब केवल संगठनात्मक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि व्यापक, सवाल और राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन चुका है, प्रदेश साहू संघ के आदेश, स्थानीय बैठकों की घोषणाएं, प्रेस विज्ञप्तियों का दौर और अब पूर्व जिलाध्यक्ष मधुसूदन प्रसाद साहू की खुली आपत्ति-इन सबके बीच समाज के भीतर एक बड़ा सवाल गुंज रहा है: आखिर 25 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व क्या 25 लोगों की बैठक से तय होगा?

पत्र नहीं मानते-चर्चा या चुनौती ?

अंदरखाने यह भी चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष के पत्र को मानने से इंकार किया गया। यदि यह बात सच साबित होती है, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि संगठन के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती मानी जाएगी, फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन समाज के द्वांदसंप्रेषण रूप से लेकर बैठकों तक यही मुद्दा सबसे ज्यादा गरमा है।

अब प्रदेश नेतृत्व की अग्निपरीक्षा

पूरा विवाद अब प्रदेश साहू संघ के अगले कदम पर टिका हुआ है। अगर इस पर सख्त और स्पष्ट फैसला नहीं आया तो आने वाले समय में हर जिला अपनी-अपनी घोषणा सभा कर सकता है, और तब शायद समाज की राजनीति में नया ट्रेंड शुरू हो जाए-जिसके पास माला ज्यादा, वही नेता ज्यादा।

समाज चाहता है नेतृत्व...रणनीति नहीं

साहू समाज का बड़ा वर्ग अब भी ऐसा नेतृत्व चाहता है जो समाज को दिशा दे, हितों की रक्षा करे और संगठन को मजबूत बनाए। लेकिन अगर प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत राजनीतिक सपनों की सीढ़ी बन गया, तो समाज का असली उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाएगा।



मधुसूदन साहू की एंट्री से विवाद और गरमाया

पूर्व जिला अध्यक्ष मधुसूदन प्रसाद साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जगदीश साहू के चुनाव को अवैधानिक बताते हुए कहा कि बिना वैधानिक प्रक्रिया और सार्वजनिक सूचना के अध्यक्ष घोषित करना नियमों के खिलाफ है, उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश संगठन के आदेश के रहते किसी भी तरह की घोषणा समाज के हजारों सदस्यों के अधिकारों को नजरअंदाज करने जैसा है। प्रेस नोट में अधिकाओं के हस्ताक्षर शामिल होने से मामला अब कानूनी बहस की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।

प्रदेश से ऊपर कौन ?

प्रदेश साहू संघ के पत्र में स्पष्ट लिखा गया था कि किसी भी विवाद की स्थिति में प्रदेश स्तर का निर्णय अंतिम होगा। इसके बावजूद अलग राह चुनने वालों ने समाज को दो हिस्सों में बांटने की जमीन तैयार कर दी है, वरिष्ठ सदस्यों का कहना है कि यह सिर्फ अध्यक्ष पद की लड़ाई नहीं, बल्कि अनुशासन बनाम महत्वाकांक्षा की जंग बनती जा रही है।

प्रदेश नेतृत्व की अग्निपरीक्षा

पूरा मामला अब प्रदेश साहू संघ के अगले कदम पर टिका गया है, यदि इस विवाद पर सख्त और स्पष्ट फैसला नहीं आया तो आने वाले समय में हर जिला अपनी-अपनी घोषणा सभा करने लगेगा, और तब शायद नया ट्रेंड बन जाए- जिसके पास माला ज्यादा, वही नेता ज्यादा।

आदेश एक तरफ...ऐतान दूसरी तरफ

31 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र साहू द्वारा जारी पत्र में कोरिया जिले की पूर्व चुनाव प्रक्रिया को निरस्त कर नई समय-सारिणी घोषित की गई थी, आदेश में साफ लिखा गया था कि मतदाता सूची, नामांकन और अंतिम चुनाव प्रक्रिया प्रदेश की निगरानी में 25 फरवरी को होगी, लेकिन कोरिया में मानो अलग ही पटकथा लिखी गई, सीमित लोगों की बैठक हुई, माला पहनाई गई और अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई, यहाँ से समाज में व्यंग्य शुरू हुआ- प्रदेश का आदेश फाइल में रह गया और माला मंच पर भारी पड़ गई।

माला पहनते ही प्रतिनिधित्व ? समाज में उठता व्यंग्य

समाज के भीतर अब सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या नेतृत्व तय करने का नया फार्मूला यही है-पहले बैठक बुलाओ, फिर माला पहनाओ और घोषणा कर दो कि यही पूरे समाज का चेहरा है? लोग तंज कसते हुए कहते नजर आ रहे हैं-आज समाज का अध्यक्ष...कल पार्टी का प्रत्याशी...और परसों विधायक का सपना, हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तेजी से राजनीतिक गलियारों में नाम उछल रहे हैं, उसने सवालियों को और धार दे दी है।

माला पहनते ही बन गया प्रतिनिधित्व ?

समाज के भीतर सबसे बड़ा व्यंग्य यही बन गया है कि प्रदेश के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ लोगों ने बैठक कर माला पहनाई और घोषणा कर दी- अब यही पूरे समाज का चेहरा है, अब लोग तंज कसते हुए पूछ रहे हैं- क्या समाज चलाने का नया फार्मूला यही है? पहले बैठक बुलाओ, फिर माला पहनाओ और अगले चुनाव में कल-हम ही 25 हजार लोगों के प्रतिनिधि हैं।

प्रदेश आदेश...या स्थानीय महत्वाकांक्षा ?

31 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र साहू द्वारा जारी पत्र में साफ कहा गया था कि चुनाव प्रक्रिया निरस्त होगी और नई व्यवस्था लागू की जाएगी, लेकिन कोरिया में मानो यह पत्र किसी फाइल का कागज भर रहा गया, प्रदेश की लाइन कटकर... और स्थानीय घोषणा दूसरी तरफ, अब समाज में यही चर्चा है- क्या कोरिया जिला संगठन प्रदेश से ऊपर हो गया है या फिर कुछ लोग खुद को नियमों से भी बड़ा समझने लगे हैं?

प्रदेश से ऊपर कौन ? सवाल जो पीछा नहीं छोड़ रहा

प्रदेश स्तर पर साफ लिखा गया था कि विवाद की स्थिति में अंतिम फैसला प्रदेश संगठन का होगा, इसके बावजूद अलग राह चुनने वालों ने न सिर्फ आदेशों को हलके में लिया बल्कि समाज को दो हिस्सों में बांटने की जमीन भी तैयार कर दी, समाज के वरिष्ठ लोग अब खुलकर कह रहे हैं, यह अध्यक्ष पद की लड़ाई नहीं, अनुशासन बनाम महत्वाकांक्षा की लड़ाई है।

समाज सेवा या 2028 की टिकट की सीढ़ी ?

कोरिया जिले की गलियों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि समाज का प्रतिनिधित्व अचानक इतना सक्रिय क्यों हो गया? क्यों अब माला, बैठक और पद की होड़ बढ़ गई? कई लोग इसे सीधा-सीधा राजनीतिक तैयारी बता रहे हैं- जहाँ समाज का मंच, सिर्फ एक लॉन्चिंग पैड बनता नजर आ रहा है, व्यंग्य में लोग कहते सुनाई दे रहे हैं-आज समाज का अध्यक्ष...कल पार्टी का प्रत्याशी...और परसों विधायक का सपना, हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तेजी से राजनीतिक गलियारों में नाम उछल रहे हैं, उसने सवालियों को और तेज कर दिया है।

सीमित बैठक, बड़ा ऐतान...वैधता पर उठे सवाल

सूत्रों का दावा है कि जिस बैठक में अध्यक्ष होने की घोषणा की गई, उसमें समाज का व्यापक प्रतिनिधित्व नहीं था। विरोधी पक्ष इसे संगठनात्मक अनुशासन की खुली अवहेलना बता रहा है, समर्थक इसे स्थानीय निर्णय कहकर सही ठहराने में लगे हैं, लेकिन सवाल वहीं है, क्या समाज की आवाज भीड़ से तय होगी या कुछ चेहरों की सहमति से?

मानिकपुर खदान में कोयला चोरी के दौरान 170 फीट नीचे गिरने से एक व्यक्ति की मौत

संवाददाता- कोरबा, 05 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। कोरबा जिले के मानिकपुर चौकी क्षेत्र स्थित एसईसीएल मानिकपुर खदान में एक मजदूर की 170 फीट की ऊंचाई से गिरने से मृत्यु हो गयी है। घटना की सूचना मिलने पर मानिकपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान मानिकपुर खदान से सटे ग्राम कुदारी निवासी 42 वर्षीय भगत कुमार मरावी के रूप में की गयी है। बताया जा रहा है कि वह कल दोपहर कोयला चोरी करने खदान में गया था। इसी दौरान वह लगभग 170 फीट नीचे सिर के बल गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। जब तक व्यक्ति काफ़ी समय तक घर नहीं लौटा, तो परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश में जुट गए। दूसरे दिन सुबह ग्रामीणों को खदान में उसका शव मिला, जिसके बाद तत्काल मानिकपुर चौकी पुलिस को सूचित किया गया। मानिकपुर चौकी प्रभारी परमेश्वर राठौर ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू की। काफ़ी मशक़त के बाद शव को खदान से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार, मृतक भगत कुमार मरावी एक पैर से दिव्यांग था और उन्हें मिर्गी की बीमारी भी थी। उसके दो छोटे बच्चे और पत्नी हैं। उनके माता-पिता का निधन हो चुका है, वह अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाला था। एसईसीएल मानिकपुर खदान से सटे ग्राम रापाखरा, कुदारी, डेलवाडीह, दादर, मानिकपुर, भिलाई खुर्द, सीतामणी और इमलीडुगू जैसे कई ग्राम और शहर से लगी बस्तियां हैं। इन क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी की जाती है, जिसे छोटे होटलों, ढाबों और बस्तियों में बेचा जाता है। कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है और परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं। मामलों में आगे की कार्यवाही की जा रही है।



अंजन माइंस प्राइवेट लिमिटेड ने अंजन हिल कोयला खदान परियोजना की जनसुनवाई संपन्न

संवाददाता- खड़गवा, 05 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। अंजन माइंस प्राइवेट लिमिटेड ने दक्षिण-पूर्वी चिरमिरी कोलफील्ड क्षेत्र में स्थित अपनी प्रस्तावित अंजन हिल कोयला खदान परियोजना के लिए जनसुनवाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह खदान कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत आती है और लगभग 388.261 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। प्रस्तावित कोयला उत्खनन के लिए जनसुनवाई 5 फरवरी को [ग्राम भुकभुकी, जनपद पंचायत खंडवा] पर आयोजित की गई, जो क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों जिनमें अरुण कलेक्टर अनिल सिदार, पर्यावरण जलवायु सरक्षण अधिकारी बुजेंद्र सारथी, स्थानीय सी एस पी दीपिका मिंज, एस ई सी एल के महा प्रबंधक श्री अशोक कुमार एवं सब परिशा मैनेजर मनीष सिंह मौजूद थे, जनसुनवाई में स्थानीय प्रतिनिधियों ने अपना समर्थन जताया जिनमें जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रिया मेश्राम ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हम खदान के खुलने का स्वागत करते हैं, एवं अन्य प्रतिनिधियों जिनमें महापौर चिरमिरी श्री राम नरेश राय, श्री संतोष सिंह



सभापति नगर निगम चिरमिरी, श्री शिवांश जैन ब्लॉक अध्यक्ष, चिरमिरी, श्रीमती गायत्री बिरहदा नेता प्रतिपक्ष नगर निगम, चिरमिरी एवं स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत शुक्ला भी शामिल थे। यह प्रक्रिया नामित अधिकारियों एवं वैधानिक प्राधिकरणों की उपस्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ और सभी नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में आयोजित की गई। परियोजना को स्थानीय निवासियों से सकारात्मक समर्थन प्राप्त हुआ, जो कंपनी की कार्यप्रणाली और प्रतिबद्धताओं के प्रति समुदाय के विश्वास को दर्शाता है। जनसुनवाई के दौरान कुछ स्थानीय निवासियों ने परियोजना के लिए निजी भूमि के संभावित अधिग्रहण को लेकर चिंता व्यक्त की। इन चिंताओं का समाधान करते हुए अंजन माइंस प्राइवेट लिमिटेड ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और परियोजना का विकास पूरी तरह से आवंटित लीज क्षेत्र के भीतर, सभी वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। अंजन माइंस प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समुदायों के समग्र विकास एवं कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन, सुरक्षा उपाय और जल प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। कंपनी ने हालिया सामुदायिक संपर्क पहलों का भी उल्लेख किया, जिनमें हुडी जैकट, स्कूल बैग और डेस्क-बैंच का वितरण शामिल है, जो क्षेत्र में शिक्षा, कल्याण और बुनियादी सामुदायिक ढांचे के समर्थन के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।



परियोजना के संचालन में आने के बाद, यह क्षेत्र में आजीविका के अवसरों के सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की अपेक्षा रखती है, साथ ही जिम्मेदार और सतत खदान प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना से संबंधित किसी प्रकार का विस्थापन, पुनर्वास या अतिक्रमण का मुद्दा नहीं है और इससे वनों, जल स्रोतों या वन्यजीवों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की अपेक्षा नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया कि परियोजना क्षेत्र में कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है, इसलिए आसपास के गांवों पर किसी नकारात्मक प्रभाव की पहचान नहीं की गई है। विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्थानीय व्यापार जगत के प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश अग्रवाल ने कहा, यह परियोजना हमारे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास अवसर है। पर्यावरणीय सुरक्षा और सामुदायिक कल्याण के अनुरूप जिम्मेदार खदान न केवल स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देगा, बल्कि चिरमिरी के व्यापारिक समुदाय की आर्थिक नींव को भी सुदृढ़ करेगा। हम अंजन माइंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ निरंतर सहयोग की आशा करते हैं, ताकि श्रमिकों और आसपास के समुदायों तक सतत लाभ सुनिश्चित हो सके। सफल जनसुनवाई के उपरांत, अंजन माइंस प्राइवेट लिमिटेड वैधानिक एवं नियामक स्वीकृतियों के अनुरूप परियोजना के अगले चरणों की ओर अग्रसर होगी और क्षेत्र में जिम्मेदार, समावेशी एवं सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय हितधारकों के साथ निकटता से कार्य करती रहेगी।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 54 लाख के इनामी 12 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

बीजापुर, 05 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गुरुवार को 54 लाख के इनामी 12 नक्सलियों ने पुलिस के आलाधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 08 महिला और 4 पुरुष कैडर के नक्सली शामिल हैं। इन्होंने 3 आटोमैटिक हथियार, कारतूस और विस्फोटक पुलिस को सौंपे। बीजापुर में सुरक्षाबलों के संयुक्त प्रयास से आज साउथ सब जौनल ब्यूरो से संबंधित कुल 54 लाख रुपये की इनामी 8 महिला और 4 पुरुष कैडर के 12 नक्सलियों, जिसमें डीवीसीएम-1 सदस्य, बटालियन नंबर 1, कंपनी नंबर दो-2, पीपीसीएम-1, एसीएम -2, पार्टी सदस्य-2, पीएलजीए सदस्य-4 ने 3 आटोमैटिक हथियार, कारतूस व विस्फोटक के साथ बस्तर आईजी सुंदरराज पट्टिलिंगम, बीजापुर एसपी डॉ. जितेंद्र कुमार यादव, उप पुलिस महानिरीक्षक केरिपु ऑफिस बीजापुर सेक्टर बीएस.नेगी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।



सुरक्षा बलों की सक्रियता और टीमवर्क

आत्मसमर्पण की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में डीआरजी बस्तर फाइटर, जिला बल, छसबल, एसटीएफ, कोबरा- 201, 204, 210 तथा केरिपु- 85, 170, 196, 199, 218, 228 एवं 229 बटालियन एवं जिले में तैनात केरिपु बलों का योगदान रहा है। इन सभी बलों ने लगातार क्षेत्र में अपनी सक्रियता, विश्वास निर्माण और संवेदनशील व्यवहार से नक्सलियों को मुखाधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है। बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने माओवादियों से अपील करते हुए कहा... नक्सली धामक और हिंसक धिंकारधारियों को त्यागकर निर्भय होकर समाज की मुख्याधारा में लौटें। शासन की 'पूना मारगेम' नीति उनके भविष्य को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान कर रही है। 'बस्तर आईजी सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि 5 फरवरी 2026 को जिला बीजापुर क्षेत्र में 'पूना मारगेम-पुनर्वास से पुनर्जीवन' अभियान के अंतर्गत सक्रिय नक्सली कैडरों द्वारा हिंसा का मार्ग त्यागकर छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति को अपनाया इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नक्सली संगठन अब तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। बस्तर आईजी ने शेष नक्सली कैडरों से अपील करते हुए कहा कि हिंसा का मार्ग केवल विनाश, पीड़ा और अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि 'पूना मारगेम' अभियान शांति, सम्मानजनक जीवन और सकारात्मक भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।

2024 से अब तक 888 नक्सली मुख्याधारा में लौट चुके हैं, 1163 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और 231 नक्सली विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले 12 नक्सलियों में- 1. 42 वर्षीय सोमड़ मड़कम, साकिन यमपुर सेण्डबोरोपरा थाना पामेड़ जिला बीजापुर पद-दरभा डिविजन डीवीसीएम(कटकल्याण एरिया कमेटी

बीजापुर, पद-कंपनी नं. 2 पार्टी सदस्य, घोषित इनामी राशि 8 लाख रुपये। 14. 24 वर्षीय आयती मड़कम ऊर्फ पुनी पति सुरेश मड़कम, साकिन पेदापाल पुरानापाय थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पद-उत्तर सब जौनल ब्यूरो पीपीसीएम, घोषित इनामी राशि 5 लाख रुपये। 15. 20 वर्षीय चमनलाल कुडियम ऊर्फ छोट्टू, साकिन मुक्कावेली थाना फरसेगढ़ जिला बीजापुर, पद-पश्चिम बस्तर डिविजन सदस्य (एसोएम), घोषित इनामी राशि 5 लाख रुपये, एसएलआर हथियार एवं 2 मैगजीन के साथ पुनर्वास। 16. 22 वर्ष पार्वती पुनेम ऊर्फ राघो, साकिन हिरौली सरपंचपारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पद-गंगालूर एरिया कमेटी सदस्य (एसोएम), घोषित इनामी राशि 5 लाख रुपये। 17. 19 वर्षीय सन्ना माड्डू, साकिन पंगुड़ स्कूलपारा थाना मोदकपाल जिला बीजापुर, पद-पश्चिम बस्तर डिविजन, घोषित इनामी राशि 2 लाख रुपये, एसएलआर हथियार और 2 मैगजीन के साथ पुनर्वास। 18. शांति कुडियम पिता विज्जा कुडियम उम्र 28 वर्ष साकिन एलीगेण्ड थाना फरसेगढ़ जिला बीजापुर, पद-नेशनल पार्क एरिया कमेटी पार्टी सदस्य, घोषित इनामी राशि 01 लाख रुपये। 19. 18 वर्षीय छोट्टी तेलम, साकिन मदपाल स्कूलपारा थाना मिरतूर जिला बीजापुर, पद-भूमनाह एरिया कमेटी पीएलजीए सदस्य, घोषित इनामी 1 लाख रुपये। 10. 18 वर्षीय जिम्मी उईका ऊर्फ अंकिता, साकिन केलमनेण्डू कड़तीपारा थाना बासागुड़ जिला बीजापुर, पद - महेड़ एरिया कमेटी पीएलजीए सदस्य, घोषित इनामी राशि 01 लाख रुपये।

माओवाद पर कड़ा प्रहार...जवानों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने छुपा था भारी मात्रा में ब्लास्ट का सामान, पुलिस ने किया जब्त



नारायणपुर, 05 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के 'हथियार निर्माण' के नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी चोट की है। डीआरजी और जिला पुलिस बल ने अबुझमाड़ के अंदरूनी इलाके में छापेमारी कर नक्सलियों द्वारा छिपाया गया हथियारों का एक विशाल डंप बरामद किया है। इस कार्रवाई को माओवाद के ताबूत में अखिरी कील माना जा रहा है।

खुफिया इनपुट पर सोनपुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई : नारायणपुर पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि थाना सोनपुर के अंतर्गत कोरसकोड़ों-पांगुड़-कंदुलपार के जंगलों में नक्सलियों ने हथियार बनाने के लिए कच्चा माल और मशीनरी छिपाकर रखी है। इस इनपुट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीआरजी की टीम ने घेराबंदी की और सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि इस क्षेत्र में बीएसएफ के साथ मिलकर स्थापित किए गए 'कोरसकोड़ों कैम्प' ने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई।

1000 किलो एल्यूमीनियम और हजारों लोहे के पाइप बरामद

जंगलों के बीच से बरामद यह डंप किसी छेटी फैक्ट्री जैसा है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में मशीनरी और कच्चा माल जब्त किया है, जिसका उपयोग नक्सली आईडी और देशी हथियार बनाने में करते थे।

- बरामद सामग्री**
- एल्यूमीनियम : लगभग 1000 किलोग्राम (विभिन्न साइज की छड़ें)।
 - लोहे के पाइप : 1200 से अधिक (बीजीएल सेल और बम बनाने हेतु)।
 - विस्फोटक सामग्री : 82 बीजीएल सेल और 46 तीर-धनुष बीजीएल।
 - मशीनरी : ग्राइंडर मशीन, इलेक्ट्रिक कटर, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर, टुलू मोटर और वेल्डिंग का सामान।
 - मैगजीन : 14 एसएलआर खाली मैगजीन और पिस्टल मैगजीन।

दंतेवाड़ा डीएसपी कल्पना वर्मा सस्पेंड कारोबारी दीपक टंडन ने अफसर पर लगाए थे करोड़ों ऐंठने, नक्सलियों की जानकारी लीक करने के आरोप

रायपुर, 05 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ शासन ने डीएसपी कल्पना वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई कारोबारी दीपक टंडन की ओर से की गई शिकायत के बाद हुई है। कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर प्यार में फंसकर करोड़ों ऐंठने और नक्सलियों की जानकारी को लीक करने का आरोप लगाया था। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद सरकार ने मामले को गंभीर मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय या शासन द्वारा निर्धारित स्थान रहेगा। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान रहेगा। 2 सप्ताह पहले इस कटौती की जांच रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी गई थी।



डीएसपी कल्पना वर्मा

कारोबारी टंडन ने 2.5 करोड़ की वस्तु, गिफ्ट मांगने का लगाया आरोप

कारोबारी दीपक टंडन ने आरोप लगाया है कि साल 2021 से महिला डीएसपी ने कथित तौर पर 'लव ट्रेप' के जरिए उनसे करीब 2.5 करोड़ रुपए की वसूली की। आरोपों में करीब 2 करोड़ रुपए कैश, एक लक्जरी कार, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख रुपए के सोने के गहने और अन्य महंगे गिफ्ट्स शामिल बताए गए हैं। कारोबारी का दावा है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कार और गहने अभी तक उसे वापस नहीं मिले हैं। उसने डीएसपी कल्पना से उन्हें वापस करने के लिए बार-बार कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कल्पना की वजह से उसे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।

बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन...6 हाईवा-ट्रैक्टर जब्त

बिलासपुर, 05 फरवरी 2026। बिलासपुर में जन प्रतिनिधियों की शिकायत, रेत माफियाओं के तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास के बाद अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने खनिज विभाग ने सक्रियता दिखाई। टीम ने घुटकू, सेंदरी सहित तनपुर इलाके में छापेमारी की। इस दौरान अवैध रेत परिवहन करने वाले तीन हाईवा और तीन ट्रैक्टर के साथ ही अवैध रूप से डंप 37 ट्रैक्टर रेत को जब्त किया गया। दरअसल, जिले में अरपा और खारून नदी समेत मस्तूरी-पचोड़े क्षेत्र स्थित नीलागर और शिवनाथ नदी में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लगातार शिकायतों के बाद भी खनिज विभाग का अमला इसे नजरअंदाज कर रहा था। इसके चलते खनिज माफियाओं का हौसला बढ़ गया। जबकि, शहर और आसपास के इलाकों में खुलेआम रेत उत्खनन और परिवहन करने लगे हैं। बता दें कि जिले में अमलडीहा, उदईबंद, सोढ़ाखुर्द और करहीकछर घाट ही वैध है। इसके बावजूद अन्य सभी घाटों से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है।



जब्त किए गए ट्रैक्टर

रायगढ़ के टायर प्लांट में ब्लास्ट...8 मजदूर 80% तक झुलसे, 9 महीने की मासूम भी जखमी, हालत नाजुक, टायर गलाने के दौरान हुआ विस्फोट

रायगढ़, 05 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित मंगल कार्बन प्लांट में टायर गलाने के दौरान जोरदार ब्लास्ट हो गया। जिसकी चपेट में आने से 8 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में एक 9 महीने की मासूम भी शामिल है। घटना खरसिया थाना इलाके के बानीपाथर की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विस्फोट इतना तेज था कि आसपास काम कर रहे लोग आग और गैस की चपेट में आ गए। सभी घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, कई मरीज 70 से 80 प्रतिशत तक झुलसे हुए हैं, जिससे उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मंगल कार्बन प्लांट में पुराने टायर पिघलाकर सड़क बनाने के लिए ऑयल तैयार किया जाता था। सुबह काम के दौरान मशीन का डबकन खोलते ही तेज धमाका हुआ।

स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत जशपुर को मिली पर्यटन विकास की बड़ी सौगात ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा मयाली : सीएम साय

रायपुर, 05 फरवरी 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की उप-योजना सीबीडीडी के अंतर्गत स्वीकृत मयाली-बगीचा विकास परियोजना का मयाली नेचर कैम्प में विधिवत भूमिपूजन किया। लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित इस परियोजना के तहत मयाली, विश्व प्रसिद्ध मधेश्वर पर्वत (विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग) तथा बगीचा स्थित कैलाश गुफा क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र की प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं जनजातीय विरासत के संरक्षण के साथ-साथ समुदाय आधारित पर्यटन को सशक्त बनाएगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जशपुर जिले को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में नई पहचान मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मयाली-बगीचा विकास परियोजना जशपुर जिले के पर्यटन



मुख्यमंत्री साय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत मयाली-बगीचा विकास परियोजना का भूमिपूजन किया।

विकास कार्यों से बढतेगी मयाली की तस्वीर, उभरेगा नया पर्यटन केंद्र

मयाली क्षेत्र को प्राकृतिक, धार्मिक एवं ग्रामीण पर्यटन के समग्र गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत 5 पर्यटक कॉटेज, कॉन्फ्रेंस एवं कंवेन्शन हॉल, स्किट डेवलपमेंट सेंटर, भव्य प्रवेश द्वार, बाउंड्री वॉल, आधुनिक टॉयलेट सुविधा, लैंडस्केपिंग एवं पाथवे का निर्माण किया जाएगा। इन सुविधाओं से पर्यटकों के उद्वार एवं विभिन्न आयोजनों की बेहतर व्यवस्था होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। धार्मिक पर्यटन को सशक्त करने के लिए शिव मंदिर क्षेत्र में प्रवेश द्वार, टॉयलेट सुविधा, लैंडस्केपिंग एवं पाथवे का विकास किया जाएगा। वहीं बगीचा स्थित कैलाश गुफा परिसर में प्रवेश द्वार, पिकनिक स्पॉट, रैपिंग शेड, घाट विकास, पाथवे तथा सीढ़ियों एवं रैलिंग का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। यह समस्त कार्य भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा संशोधित स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत मयाली-बगीचा विकास परियोजना के माध्यम से किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण होने से पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती तथा क्षेत्र की सांस्कृतिक-प्राकृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की संभावना है।

संस्कृति को देश-दुनिया के पर्यटकों तक पहुंचाया जाएगा। पर्यटन से होने वाली आय का सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। इससे न केवल पर्यटन क्षेत्र के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आई है। स्किट डेवलपमेंट सेंटर में टूर गाइड, होटल सेवा, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हस्तशिल्प एवं डिजिटल जुड़कर आय अर्जित कर सकेंगे और

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ढाढाचारा का आरोप-कांग्रेस ने उठाए सवाल सुबोध ने कहा...बिना टेंडर साइंस कॉलेज मैदान में करोड़ों का हो रहा काम...

रायपुर, 05 फरवरी 2026। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल ने प्रेसवार्ता में दावा किया कि इस योजना के तहत होने वाले आयोजन में भ्रष्टाचार किया गया है और बिना नियमों के करोड़ों रुपये का काम कराया जा रहा है। सुबोध हरितवाल ने कहा कि 10 फरवरी को साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भरी अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आयोजन के लिए निविदा (टेंडर) प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जबकि नियमानुसार CSID के माध्यम से कंपनियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को सिर्फ 5 कंपनियों को आमंत्रित किया गया और उन्हें 24 घंटे के भीतर डिजाइन प्रेजेंटेशन के साथ प्रस्तुत होने को कहा गया। सुबोध हरितवाल ने सवाल उठाया कि ऐसा कौन-सा डिजाइन और लेआउट है, जो पहले से ही पास हो चुका है।



सुबोध ने कहा...जंजूरी जैसा हो रहा ढाढाचारा

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बिना टेंडर के साइंस कॉलेज मैदान में काम शुरू हो चुका है, जबकि इस आयोजन पर 5 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी आयोजन में 4-5 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं और निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार है। सुबोध ने इसे 'जंजूरी भ्रष्टाचार 2.0' करार देते हुए कहा कि जैसे जंजूरी मामले में अनियमितताएं सामने आई थीं, वैसे ही इस मामले में भी गड़बड़ी हुई है।

मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि साइंस कॉलेज मैदान प्रशासन की ओर से वर्क ऑर्डर पर मिलता है, ऐसे में क्या इसे पहले ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में महिला बल विकास मंत्री के विभाग को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और कहा कि विभाग की सल्लिसता के बिना ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दौड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने गिनाई दो साल की उपलब्धियां...बोले-4500 करोड़ का फ्री इलाज, 1600 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति, 30 से अधिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत

रायपुर, 05 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में पिछले दो सालों में किए गए काम के बारे में आज हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में 1600 से अधिक डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की गई है। 30 से ज्यादा नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति, आयुष्मान भारत योजना के तहत 4500 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज किया गया है।



अस्पताल, 2 सिविल अस्पताल (220 बिस्तर), 8 सिविल अस्पताल (100 बिस्तर), 1 मानसिक अस्पताल (200 बिस्तर, सेन्ट्री), 1 MCH अस्पताल, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 11 प्राथमिक

स्वास्थ्य केंद्र, 34 उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही 12 IPHL लैब, 31 BPHU, 1 क्रिटिकल हेल्थ केयर ब्लॉक भी मंजूर किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पिछले दो वर्षों में करीब 3 लाख आरोग्य मेले आयोजित किए गए, जहां इलाज के साथ वेलनेस सुविधाएं भी दी गईं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पिछले दो वर्षों में करीब 3 लाख आरोग्य मेले आयोजित किए गए, जहां इलाज के साथ वेलनेस सुविधाएं भी दी गईं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ केयर ब्लॉक भी मंजूर किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पिछले दो वर्षों में करीब 3 लाख आरोग्य मेले आयोजित किए गए, जहां इलाज के साथ वेलनेस सुविधाएं भी दी गईं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ केयर ब्लॉक भी मंजूर किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पिछले दो वर्षों में करीब 3 लाख आरोग्य मेले आयोजित किए गए, जहां इलाज के साथ वेलनेस सुविधाएं भी दी गईं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ केयर ब्लॉक भी मंजूर किए गए।

किए गए, जहां इलाज के साथ वेलनेस सुविधाएं भी दी गईं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ केयर ब्लॉक भी मंजूर किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पिछले दो वर्षों में करीब 3 लाख आरोग्य मेले आयोजित किए गए, जहां इलाज के साथ वेलनेस सुविधाएं भी दी गईं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ केयर ब्लॉक भी मंजूर किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पिछले दो वर्षों में करीब 3 लाख आरोग्य मेले आयोजित किए गए, जहां इलाज के साथ वेलनेस सुविधाएं भी दी गईं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ केयर ब्लॉक भी मंजूर किए गए।